दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

अपीलीय सिविल

रणजीत सिंह सरकारिया, नयायाधिपती के सामने.

दयाल दास,-अपीलकर्ता।

बनाम

संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य,-प्रतिवादी।

निष्पादन द्वितीय अपील संख्या 1964 की 1513

16 अप्रैल, 1968.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V)—एस. 11—ट्रायल कोर्ट क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद एक डिक्री पारित करता है—उच्च न्यायालय के अधिकार पर आधारित ऐसा निर्णय—उच्च न्यायालय के प्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया—क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति—क्या निष्पादन न्यायालय में लिया जा सकता है—रेज्युडिकाटा का बार— क्या ऐसी आपत्ति पर लागू होता है - निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम (1950 का XXXI, 1960 के अधिनियम द्वारा संशोधित) -5। 8(2-ए)-"निष्क्रिय संपत्ति के रूप में निहित होने का तात्पर्य"-का अर्थ।

यह निर्धारित किया गया कि इस मूल सिद्धांत के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है और इसकी अमान्यता तब स्थापित की जा सकती है जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, यहां तक कि उस स्तर पर भी निष्पादन की और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी। अधिकार क्षेत्र का दोष, विशेष रूप से जब यह कार्रवाई के विषय के संबंध में हो, तो किसी भी डिक्री को पारित करने के न्यायालय के अधिकार पर प्रहार करता है। लेकिन निष्पक्षता और ठोस सार्वजनिक नीति के आधार पर एक और समान रूप से महत्वपूर्ण और कोई कम मौलिक सिद्धांत नहीं है, अर्थात, जबकि मनुष्य नश्वर हैं, मुकदमेबाजी को अमर नहीं बनने दिया जा सकता है, इसके

दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

मद्देनजर पार्टियों के लिए बार-बार वही मामला, और न्यायिक प्रक्रिया में एक असंगत अप्रत्याशितता और अंतहीन खीझ पैदा होती है। उस सिद्धांत के अनुसार, यदि मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकार के बारे में कोई आपत्ति उठाई गई थी, और ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी जांच और प्रतियोगिता के बाद अंततः उस पर फैसला सुनाया गया था, तो उस मुद्दे पर दिया गया निर्णय, जब तक कि अपील या पुनरीक्षण में उलट या संशोधित न हो , पार्टियों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है, और मामले को उनके द्वारा बाद के मुकदमे में दोबारा नहीं उठाया जा सकता है, उसी कार्यवाही के बाद के चरण में, या उसी डिक्री के निष्पादन में तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय उच्च न्यायालय के प्राधिकार पर आधारित हो और बाद में उस प्राधिकार को खारिज कर दिया गया हो, फिर भी यह इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को पक्षों के बीच पुनर्निर्णय के रूप में कार्य करने से नहीं रोकेगा। यहां तक कि कानून के किसी प्रश्न पर एक गलत निर्णय भी पुनर्निर्णय है क्योंकि यह निर्णय है न कि तर्क जो पुनर्निर्णय के रूप में कार्य करता है।

[पैरा 3]

यह निर्धारित किया गया कि निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 8 (2-ए) में वाक्यांश "निष्क्रिय संपत्ति के रूप में निहित होने का तात्पर्य है" जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है या कानून में स्पष्ट ना होते हुए भी स्पष्ट है, उसका सूचक है। वाक्यांश के व्यापक आयाम के बावजूद, इसका एक अनिवार्य तत्व यह है कि कस्टोडियन में निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निहित होने के बाहरी अभिव्यक्ति के कुछ प्रथम दृष्टया सबूत या कार्य संकेतक होने चाहिए।

[पैरा 9]

निष्पादन श्री ई.एफ. बारलो, जिला फ़ज, करनाल की अदालत के 5 अक्टूबर, 1964 के फैसले से दूसरी अपील, अतिरिक्त उप-न्यायाधीश, तृतीय श्रेणी, करनाल के 3 जून, 1964 के आदेश की पुष्टि करते हुए, आपत्ति याचिका को सिविल प्रक्रिया संहिता; धारा 47 के तहत खारिज कर दिया, निर्णय-देनदार द्वारा दायर किया गया।

सीएच. रूप चंद, वकील; अपीलकर्ता के लिए.

डी. एन. अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए आनंद सरूप, महाधिवक्ता (एच आर्यना) जे.सी. वी. एर्मा, अधिवक्ता के साथ।

आदेश

सरकारिया, नयायाधिपती.-यह निष्पादन दूसरी अपील निम्नलिखित परिस्थितियों से उत्पन्न होती है: -

नियादार माई पियारे लाई ने 9 फरवरी, 1960 को तय किए गए 1959 के सूट नंबर 494 में दयाल दास के खिलाफ, करनाल के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत से कब्जे की डिक्री प्राप्त की। डिक्री धारक ने 28 फरवरी, 1968 को डिक्री का निष्पादन किया। दयाल दास- फैसले-देनदार ने आपत्ति जताई कि 9 फरवरी, 1960 की उपरोक्त डिक्री, अमान्य होने के कारण निष्पादन योग्य नहीं थी क्योंकि यह एक ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जिसके पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। आपत्ति दोतरफा थी: (1) डिक्री पारित करने के सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 46 के तहत वर्जित किया गया था; और (2) डिक्री को अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2-ए) के प्रावधानों द्वारा अमान्य कर दिया गया था, जिसे बाद में 1960 के संशोधन अधिनियम 1 द्वारा डिक्री के पारित होने के बाद प्रभावी किया गया था। निष्पादन न्यायालय ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। निर्णय-ऋणी अपील में जिला न्यायाधीश, करनाल के सामने गया। बाद वाले ने अपील खारिज कर दी और निष्पादन न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। इसलिए निर्णय-देनदार द्वारा यह दूसरी अपील है।

(2) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि जिस मुकदमे में डिक्री पारित की गई थी, उसे सुनने और निर्धारित करने का ट्रायल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पहले से ही अधिनियम की धारा 46 के तहत वर्जित था। इस तर्क के समर्थन में, कस्टोडियन ***इवैक्यू प्रॉपर्टी पंजाब और अन्य बनाम जाफरान बेगम***[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर भरोसा किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि जहां डिक्री को पारित करने वाले न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी होती है, वहां निष्पादन की कार्यवाही में भी किसी भी स्तर पर आपत्ति ली जा सकती है। इस

---

[1] 1968 PX.R. 1.

दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

तर्क के समर्थन में वकील ने ***किरण सिंह एवं अन्य बनाम चमन पासवान एवं अन्य***[2] का हवाला दिया है।

(3) मुझे इस मूल सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है और इसकी अमान्यता तब स्थापित की जा सकती है जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, यहां तक कि निष्पादन के चरण में भी और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी। क्षेत्राधिकार का दोष, विशेष रूप से जब यह कार्रवाई के विषय के संबंध में हो, तो किसी भी डिक्री को पारित करने के न्यायालय के अधिकार पर प्रहार करता है। लेकिन निष्पक्षता और ठोस सार्वजनिक नीति के आधार पर एक और समान रूप से महत्वपूर्ण और कोई कम मौलिक सिद्धांत नहीं है, अर्थात, जबकि मनुष्य नश्वर हैं, मुकदमेबाजी को अमर नहीं होने दिया जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप बार-बार और अंतहीन परेशानी आती है और एक ही मामले में पक्ष-विपक्ष, और न्यायिक प्रक्रिया में चिंताजनक अप्रत्याशितताहोती है। उस सिद्धांत के अनुसार, यदि मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकार के बारे में कोई आपत्ति उठाई गई थी, और ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी जांच और प्रतियोगिता के बाद अंततः उस पर फैसला सुनाया गया था, तो उस मुद्दे पर दिया गया निर्णय, जब तक कि अपील में उलट या संशोधित न किया गया हो या पुनरीक्षण, पार्टियों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है, और मामले को उनके द्वारा बाद के मुकदमे में दोबारा नहीं उठाया जा सकता है, उसी कार्यवाही के बाद के चरण में, या उसी डिक्री के निष्पादन में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मामलों में, निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जाने से इनकार कर देगा और मुकदमे में अंततः तय किए गए मामले को फिर से खोल देगा। बिल्कुल यही स्थिति यहां है। मुकदमे में, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति की गई। इस मुद्दे पर एक मुद्दा तैयार किया गया था; उस मुद्दे पर साक्ष्य पेश किए गए, और उस पर सुनवाई की गई और अंततः वादी के पक्ष में निर्णय दिया गया। पहले, इस मुद्दे पर, न्यायिक निर्णय में कुछ विरोधाभास था। उस संघर्ष को निपटाने के लिए इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा ***एमएसटी जाफरान बेगम बनाम कस्टोडियन, इवैक्यू प्रॉपर्टी***[3] में माना गया कि कस्टोडियन अंततः स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं कर सकता, भले ही वह उपरोक्त अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में उचित रूप से उठा हो। पूर्ण पीठ का अनुपात निचली अदालतों पर बाध्यकारी होने के कारण, इस अपील में दिए गए आदेशों को पारित करने में उनके द्वारा पालन किया गया था।

---

[2] A.I.R. 1954 SC 340

[3] I.L.R. (1963) 1 Punj. 281=1962 P.L.R. 709.

दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

(4) यह सच है कि बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने ***(जाफरान बेगम के मामले में) (1)*** पूर्ण पीठ के उपरोक्त फैसले को कानून की दृष्टि से गलत पाया। लेकिन यह इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को न्यायिक के रूप में संचालित होने से नहीं रोकेगा। इस प्रस्ताव में अधिकार है कि कानून के प्रश्न पर एक गलत निर्णय भी संबंधित पक्षों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है। न्यायिक निर्णय की शुद्धता या अन्यथा का इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि यह न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है या नहीं, क्योंकि यह निर्णय है, न कि वह तर्क जिस पर यह आधारित है, जो निर्णय के रूप में कार्य करता है।

(5) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ***बेनॉय कृष्ण मुखर्जी बनाम मोहन लाल गोयनका***[4] के रूप में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले में यह विचार किया है कि आसनसोल न्यायालय में आयोजित निष्पादन कार्यवाही उस न्यायालय में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी के कारण शून्य और निष्क्रिय थी, और ऐसी याचिका को पूर्व न्यायिक सिद्धांत के आधार पर वर्जित नहीं किया गया है। उस निष्कर्ष को उलटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पार्टियों के बीच पिछले निष्पादन मामले में एक निर्णय, अर्थात्, मामला निष्पादन न्यायालय की क्षमता के भीतर नहीं था, भले ही गलत हो, पार्टियों पर बाध्यकारी है***- मोहनलाल गोयनका बनाम बेनॉय कृष्णा मुखर्जी और अन्य***[5]***,*** गुलाम हसन, न्यायाधीश, ने पैरा 26 में कहा:-

"वर्तमान मामले में जो सवाल उठता है वह यह नहीं है कि क्या आसनसोल में निष्पादन अदालत के पास निष्पादन आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था या नहीं, बल्कि यह है कि क्या निर्णय-देनदार को रचनात्मक 'पुनर्न्याय' के सिद्धांत द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रश्न को उठाने से रोका गया है। हम तदनुसार मानते हैं कि 'पुनर्न्याय' के प्रश्न पर न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है।"

(6) यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सिविल कोर्ट के पास कुछ क़ानूनों द्वारा प्रतिबंधित होने से पहले लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही की सुनवाई के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का फैसला करने की शक्ति है, भले ही जांच से पता चले कि उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। (***मेसर्स भाटिया ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लिमिटेड बनाम डी.सी. पटेल***[6] को देखें। वर्तमान मामले में, क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर सुनवाई की गई और अंततः न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करते हुए

[4] A.I.R. 1950 Cal. 287
[5] AJ.R. 1953 S.C. 65
[6] A.I.R. 1963 SC 16

निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मोहन-लाल गोयनका का मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिक मजबूती से लागू होता है। जबकि मोहनलाल गोयनका के मामले में, पुनर्न्याय का सिद्धांत रचनात्मक रूप से लागू किया गया था, मेरे सामने वाले मामले में यह सीधे लागू होगा। विद्वान वकील का पहला तर्क अपीलार्थी के टिकाऊ न होने के कारण खारिज की जाती है।

(7) जहां तक दूसरे विवाद का संबंध है, न्यायिक निर्णय का सिद्धांत रचनात्मक या सीधे तौर पर लागू नहीं होगा। प्रश्नगत डिक्री के पारित होने के बाद अधिनियम की धारा 8 में एक संशोधन द्वारा उपधारा (2-ए) डाली गई थी। इसलिए, इसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं ले जाया जा सका। संशोधन की भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी होना था। यह उपधारा (2-ए) कहती है:-

"(2-ए) उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संपत्ति जो किसी भी कानून के तहत निरस्त की गई है, किसी भी राज्य में कस्टोडियन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति में निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निहित होने का तात्पर्य है। ऐसे कानून या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी भी दोष या अमान्यता के बावजूद, सभी उद्देश्यों के लिए वैध रूप से उस व्यक्ति में निहित माना जाएगा, जैसे कि ऐसे कानून के प्रावधान संसद द्वारा अधिनियमित किए गए थे और ऐसी संपत्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत घोषित निष्क्रांत संपत्ति मानी जाएगी और तदनुसार ऐसी संपत्ति के संबंध में कस्टोडियन या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश या अन्य कार्रवाई वैध और विधिपूर्वक बनाया या लिया गया माना जाएगा।"

(8) उप-धारा (2-ए) 1960 के अधिनियम 1 की धारा 2 द्वारा पेश की गई थी, जो 27 फरवरी, 1960 को लागू हुई। इसका उद्देश्य कुछ प्रांतीय या राज्य कानून के तहत निहित होने के मामले में संभावित दोषों को ठीक करना है। इन प्रांतीय या राज्य कानूनों की वैधता संदिग्ध थी। 17 अप्रैल, 1950 से पहले, यानी 1950 के केंद्रीय अधिनियम 34 के प्रारंभ होने से पहले, प्रांतीय या राज्य कानूनों के तहत कस्टोडियन में मूल दोषपूर्ण निहित को मान्य करने के लिए, उपधारा में "निहित होने का तात्पर्य" शब्द पेश किए गए थे। "अभिप्राय" शब्द का व्यापक अर्थ है। इसके शब्दकोश अर्थ में, इसका अर्थ है, 'अपने अर्थ के रूप में बताना'; 'व्यक्त करना, संकेत करना या बाहरी रूप से प्रकट करना', इरादा करने, दावा करने आदि का आभास होना।'

दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

(9) जैसा कि ***अज़ीमुन्निसा बनाम डिप्टी कस्टोडियन***[7] में , सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बताया गया है, इसका मतलब है "उपकरणों के चेहरे पर क्या दिखाई देता है;" स्पष्ट और कानूनी आयात नहीं"। यह इस बात का सूचक है कि ऊपर से क्या दिखता है या स्पष्ट है, भले ही क़ानूनी तौर पर ऐसा न हो। वाक्यांश "निष्क्रिय संपत्ति के रूप में निहित होने का तात्पर्य" के व्यापक आयाम के बावजूद, इसका एक अनिवार्य तत्व यह है कि कस्टोडियन में निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निहित होने के बाहरी प्रकटीकरण का संकेत देने वाले कुछ प्राइम जेड साक्ष्य या कार्य होने चाहिए। मेरे सामने आए मामले में, नीचे की दोनों अदालतों ने इसे एक तथ्य के रूप में पाया है कि इस मामले में ऐसे प्रथम फीके साक्ष्य का भी अभाव था। नीचे दिए गए न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष यह है कि जहां तक विवाद में दुकान (संख्या 748), जिस पर दयाल दास निर्णय देनदार द्वारा दावा किया गया है, का संबंध है, इसे 'संरक्षक के प्रासंगिक रजिस्टर में निष्क्रांत संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया गया था'। जिला न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार की है: -

"दयाल दास के खिलाफ मुकदमे में पूरी तरह से अलग स्थिति है। वादी के अनुसार, वाद में संपत्ति संख्या 748 है, जिसे प्रदर्शनी पृष्ठ 4 में 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया है, न कि 749 जो कि 748 के उत्तर की ओर है। वाद में भी, वाद में संपत्ति की सीमा उत्तर की ओर है। वादी की दुकान दर्शाई गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वादी ने दुकान संख्या 748 के लिए मुकदमा दायर किया है, न कि 749 के लिए। अवतार सिंह के बयान के अनुसार, संपत्ति संख्या 748 को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। केवल 749 ही दर्ज किया गया है। नंबर 749 को लेकर भी इसे हिंदू संपत्ति के तौर पर दिखाया गया है। इस प्रकार, मुकदमे में यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति नहीं है।"

(10) इन परिस्थितियों में, न्यायालयों का निष्कर्ष सही है, कि दुकान संख्या 748 निष्क्रांत संपत्ति नहीं होने के कारण, कस्टोडियन में 'निहित होने का उद्देश्य' नहीं था। इस प्रकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2-ए) अपीलकर्ता के लिए कोई लाभकारी नहीं है। परिणाम यह हुआ कि अपील विफल हो गई और इसे खारिज कर दिया गया। इसमें शामिल कानूनी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

[7] A.I.R. 1961 SC 365

दयाल दास बनाम संयुक्त हिंदू परिवार फर्म, जिसे नियादर मल-पियारा लाल के नाम से जाना जाता है और अन्य (सरकारिया, नयायाधिपती)

<u>अस्वीकरण :</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरुक्षेत्र, हरियाणा